सत्यमेव जयते

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

क्षेत्रीय कार्यालय – राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, उत्तराखण्ड, चण्डीगढ़, दमन एवं दीव
Regional Office- Rajasthan, Gujarat, Haryana, Punjab, Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir, Uttarakhand, Chandigarh, Daman & Diu
कमरा न. 101 व 102, प्रथम तल, खण्ड – ए, केन्द्रीय सदन, सेक्टर–10, विधाधर नगर, जयपुर – 302023
Room No. 101 & 102, 1st Floor, Block -A, Kendriya Sadan, Sector - 10, Vidyadhar Nagar, Jaipur-302023
दूरभाष एवं फैक्स न. – 0141–2235488, Telefax : 0141-2235488

पत्रावली संख्या/File No.: 6/2/राप्र./4/2011–आर.यू. दिनांक/Date: 27.5.13

सेवामें,

निजी सचिव
माननीय अध्यक्ष महोदय
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
भारत सरकार
छठी मंजिल, लोकनायक भवन
खान मार्केट, नई दिल्ली – 110003

विषय – माननीय डॉ. रामेश्वर उरॉव, अध्यक्ष, महोदय की दिनांक – 27/04/2013 से 02/05/2013 तक जिला – उदयपुर एवं बांसवाड़ा, राजस्थान के राजकीय प्रवास की रिपोर्ट।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आयोग के माननीय अध्यक्ष, की दिनांक – 27/04/2013 से 02/05/2013 तक जिला – उदयपुर एवं बांसवाड़ा (राजस्थान) के राजकीय प्रवास की तैयार की गई रिपोर्ट सलंग्न कर अध्यक्ष महोदय के अवलोकनार्थ एंव अनुमोदनार्थ प्रेषित् है।

सलंग्न – यथोपरि।

भवदीय
(वेदप्रकाश सिंहल)
अनुसंधान अधिकारी

This may be put up on file & pls by Section
JS. May kindly see at draft stage.
DD
Pl. host it on website after approval of Chairperson.
JS
DDKDB
29/5/13
752/CP/2013
30/6/2013
Dir (RU-II)
Pl. put up on file for perusal & approval of CP.
3/6
Pl. put up on file
3/6

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

डॉ. रामेश्वर उराँव, अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली के दिनांक – 27/04/2013 से 02/05/2013 तक राजस्थान के जिला – उदयपुर एवं बांसवाड़ा राजकीय प्रवास की रिपोर्ट।

डॉ. रामेश्वर उराँव, अध्यक्ष, श्री भैरूलाल मीना, सदस्य एवं श्रीमती के. डी. बंसौर, उपनिदेशक, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग दिनांक – 27/04/2013 को वायुयान द्वारा दिल्ली से सायं 5.15 बजे उदयपुर (डबोक हवाई अड्डे) पहुँचे। उदयपुर पहुँचने पर नामित प्रोटोकॉल अधिकारी श्री भोज कुमार (प्रोजेक्ट अधिकारी, टी. ए. डी.), श्री लाल सिंह, उपखण्ड अधिकारी, मावली एवं श्री वी. पी. सिंहल, अनुसंधान अधिकारी, आयोग क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर ने स्वागत किया। मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर के कुलपति श्री आई. वी. त्रिवेदी ने भी उदयपुर हवाई अड्डे पहुँच कर स्वागत किया।

दिनांक – 27/04/2013 को सांय हवाई अड्डे से सर्किट हाउस, उदयपुर पहुँचने के पश्चात् श्री सुबोध अग्रवाल, सम्भागीय आयुक्त व आयुक्त जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, उदयपुर ने अध्यक्ष महोदय से शिष्टाचार भेंट की व जनजाति उपयोजना क्षेत्र में क्रियान्वित योजनाओं पर प्रकाश डाला।

दिनांक – 28/04/2013

मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर आयोजित अनुसूचित जाति/जनजाति प्रतिभावान छात्र/छात्राओं के लिए सम्मान समारोह –

दिनांक – 28/04/2013 को अध्यक्ष महोदय व सदस्य महोदय ने मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर के अनुसूचित जाति तथा जनजाति प्रकोष्ठ द्वारा विश्वविद्यालय के अनुसूचित जाति/जनजाति प्रतिभावान छात्र/छात्राओं के सम्मान समारोह में भाग लिया। सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि माननीय अध्यक्ष थे। इस समारोह में अन्य विशिष्ट अतिथि न्यायमूर्ति श्री पी. एन. दवे, सेवानिवृत न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय, श्री पी. आर. सिसोदिया, सयुंक्त सचिव, मानव संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार, श्री मांगीलाल गरासिया, खेल राज्यमंत्री, राजस्थान सरकार, श्री रघुवीर सिंह मीना, सांसद एवं श्री आई. वी. त्रिवेदी, कुलपति, मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय थे। इस सम्मान समारोह में विश्वविद्यालय द्वारा सत्र 2006–07 से 2010–11 तक के स्नातक एवं स्नातकोत्तर परीक्षाओं में 65% अथवा इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले एवं नेट, स्लेट, एम.फिल, पी. एच. डी. तथा राष्ट्रीय स्तर पर खेलमें सहभागिता देने वाले अनुसूचित जाति/जनजाति के विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। जिसमें 74 नेट/जे. आर. एफ./स्लेट 83, पी.एच.डी./एम.फिल, 2 खेल, स्नातकोत्तर,

Rameshwar Oraon
Dr. RAMESHWAR ORAON
Chairperson
National Commission for Scheduled Tribes
Govt. of India
New Delhi

44 स्नातक, 242 बी. एड. व 1 बी. पी. एड. के विद्यार्थियों सहित कुल 456 विद्यार्थियों को प्रशस्ति पत्र एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। सम्मान समारोह के प्रारम्भ में विश्वविद्यालय अनुसूचित जाति/जनजाति प्रकोष्ठ के समन्वयक डॉ. हनुमान प्रसाद ने बताया कि सत्र 2012–13 में प्रकोष्ठ को स्टेण्डिग कमेटी ने विभिन्न पाठ्यक्रमों के प्रवेश में आरक्षण, छात्रावास में प्रवेश, छात्रवृत्ति आदि हेतु महाविद्यालयों में जाकर आरक्षण प्रावधानों को लागू करने की सुनिश्चितता तय की। विश्वविद्यालय के कुलपति श्री आई. वी. त्रिवेदी ने अपने उद्‌बोधन में बताया कि विश्वविद्यालय में सत्र 2010–11 में 22885 अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राऐं अध्ययनरत थे। यह संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। विद्यार्थियों को आकाश टेबलेट पीसी देने के पूर्व में दिये गये आश्वासन के सम्बन्ध में विशिष्ट अतिथि श्री आर. पी. सिसोदिया, सयुंक्त सचिव, भारत सरकार ने कहा कि कुछ तकनीकी कारणों से विद्यार्थियों को आकाश टेबलेट पीसी उपलब्ध कराने में विलम्ब हो रहा है।

समारोह के मुख्य अतिथि आयोग के माननीय अध्यक्ष महोदय ने सम्मान समारोह में आमंत्रित करने के लिए विश्वविद्यालय का आभार प्रकट किया। उन्होने **शिक्षा की प्रतिशतता बढ़ने के उपरान्त भी देश में घट रही समसामयिक घटनाओं पर चिन्ता व्यक्त की तथा नारी शिक्षा पर जोर दिया। उन्होने बताया कि शिक्षा का उद्धेश्य मात्र डिग्री प्राप्त करना, नौकरी लेना व धन कमाना नहीं है बल्कि साथ ही चरित्र निर्माण व जीवन का चहुँमुखी विकास भी होना चाहिये।**

उन्होने युवाओं को लक्ष्य निर्धारित कर उस पर पूरा ध्यान केन्द्रित करने के लिए प्रेरित किया। उन्होने युवाओं को अपनी ऊर्जा सकारात्मक कार्यों में लगाने का आव्हान किया, जिससे हमारा समाज एवं राष्ट्र खुशहाल रह सके। उन्होने युवाओं के राजनीति में भाग लेने के सम्बन्ध में स्पष्ट किया कि वे देश व समाज में बदलाव का कारक बने व देश को सही दिशा प्रदान करने में सहयोगी बने। सम्मान समारोह में आयोग के माननीय सदस्य सहित अन्य विशिष्ठ अतिथिगणों ने भी सम्बोधित किया।

जिला – बांसवाड़ा

दिनांक – 29/04/2013

दिनांक – 29/04/2013 को प्रातः अध्यक्ष एवं सदस्य महोदय आदिवासियों के तीर्थ स्थल बेणेश्वर धाम होते हुए ग्राम – जगपुरा, पंचायत समिति – घाटोल, जिला – बांसवाड़ा पहुँचे।

राजकीय जनजाति बालिका आश्रम छात्रावास, जगपुरा, पंचायत समिति – घाटोल के नवनिर्मित भवन का उद्‌घाटन –

राजकीय जनजाति बालिका आश्रम छात्रावास, जगपुरा, पंचायत समिति – घाटोल, जिला – बांसवाड़ा में माध्यमिक स्तर की जनजाति बालिकाओं के लिए केन्द्रीय प्रवर्तित योजना अन्तर्गत 1.77 करोड़ की लागत से बने बालिका छात्रावास के नवनिर्मित भवन का माननीय अध्यक्ष

Rameshwar Oraon
Dr. RAMESHWAR ORAON
Chairperson
National Commission for Scheduled Tribes
Govt. of India
New Delhi

महोदय ने लोकार्पण किया। इस अवसर पर राजस्थान सरकार के जनजाति विकास एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीय, जिला प्रमुख श्रीमती रेशम मालवीय, श्री नाना लाल निनामा, विधायक घाटोल तथा अन्य गणमान्य लोग भी उपस्थित थे। इस छात्रावास की क्षमता 50 छात्राओं की है तथा वर्तमान में एक अधीक्षका तथा एक कोच स्टाफ की स्वीकृति राज्य सरकारके प्रक्रियाधीन है। छात्रावास में निवासित छात्राओं को निःशुल्क आवास, भोजन, पोशाक एवं अन्य सुविधाऐं उपलब्ध कराने हेतु राज्य सरकार 1750/– रूपये प्रतिमाह प्रति छात्रा की दर से (अधिकतम 10 माह तक प्रत्येक सत्र में) व्यय करेगी। छात्रावास में प्रवेश प्रक्रिया मई–जून, 2013 में प्रारम्भ होगी। माननीय अध्यक्ष, सदस्य तथा अन्य गणमान्य अतिथियों ने ग्राम – जगपुरा में आदिवासियों की जनसभा को भी सम्बोधित किया। माननीय अध्यक्ष ने इस अवसर पर शिक्षा तथा विशेष तौर पर नारी शिक्षा पर जोर दिया तथा आशा प्रकट की कि क्षेत्र के आस–पास की जनजाति छात्राऐं इस छात्रावास के माध्यम से राजस्थान सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाओं का भरपूर लाभ उठाते हुए शिक्षा अर्जन को जारी रखेगी। आयोग के माननीय सदस्य श्री भैरूलाल जी मीना ने भी इस अवसर पर ग्रामीण समुदाय को सम्बोधित किया।

रणछोड़ दासजी मंदिर के पास घाटोल में कॉजवे (पुलिया) का शिलान्यास

अपरान्ह 12.30 बजे घाटोल जिला – बांसवाड़ा में अध्यक्ष महोदय ने जनजाति विकास विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा स्वीकृत रूपये 353.00 लाख राशि से बनने वाले कॉजवे (पुलिया) का शिलान्यास किया। इसके अन्तर्गत 350 मीटर लम्बा वेन्टेड कॉजवे (1000 मिमी व्यास के आर. सी.सी ह्यूम पाईप) तथा लगभग 1.5 किमी लम्बाई में डामरीकरण का कार्य प्रस्तावित है। उक्त कार्य की निविदा की प्रक्रिया मई, 2013 में पूर्ण कर ली जायेगी। **इस कॉजवे के बन जाने से जिला – बांसवाड़ा व डूँगरपुर की लगभग 10 से 13 पंचायतों के क्षेत्रवासियों का सीधा सम्पर्क हो जायेगा तथा मोटा गांव (मार्केटिंग सेन्टर) आने के लिए ग्राम वासियों को लगभग 15 किमी घूमकर आने की समस्या से निजात मिल पायेगा।**

माननीय अध्यक्ष ने ग्रामीण आदिवासी समुदाय के लिए किये जा रहे इस कार्य को ग्रामीणों के आवागमन की दृष्टि से बहुत उपयोगी बताया तथा राज्य सरकार के इस कदम की सराहना की। अध्यक्ष महोदय ने इस कार्य को तय समयावधि में पूरा करने हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग को कहा।

ग्राम – कण्ठाव (घाटोल) में ए. एन. एम. आवास का उद्घाटन :

माननीय अध्यक्ष महोदय ने ग्राम – कण्ठाव (घाटोल), जिला – बाँसवाड़ा में रूपये 3.25 लाख राशि से बी. आर. जी. एफ. योजना के अन्तर्गत निर्मित ए. एन. एम. आवास का लोकापर्ण किया। यह भवन वर्ष 2010–11 में स्वीकृत हुआ था। अध्यक्ष महोदय ने इस अवसर पर कहा कि ए. एन. एम. आवास बन जाने से ग्राम कण्ठाव व आस–पास के ग्रामीण आदिवासियों को ए. एन. एम. द्वारा प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य व चिकित्सा सुविधाओं का 24 घण्टे लाभ

Rameshwar Oraon

Dr. RAMESHWAR ORAON
Chairperson
National Commission for Scheduled Tribes
Govt. of India
New Delhi

प्राप्त होगा तथा उन्होने इस आवास में रहने वालो ए. एन. एम. की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा ध्यान रखने की आवश्यकता बताई।

वृहत बहुउद्धेशीय सहकारी समीति भवन ग्राम पंचायत – कण्ठाव, पंचायत समिति – घाटोल का शिलान्यास :

ग्राम – कण्ठाव में ही 10 लाख रूपये की लागत से बनने वाले वृहत बहुउद्धेशीय सहकारी समिति भवन का शिलान्यास माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा किया गया।

अध्यक्ष महोदय ने इस अवसर पर जन समूह को सम्बोधित करते हुए कहा कि इस लैम्पस के शुरू हो जाने पर आदिवासियों को लैम्पस के माध्यम से खाद बीज व कीटनाशक औषधियाँ वँही सुलभ हो सकेगी तथा लघु वन उपज संग्रहण में उसकी मुख्य भूमिका होगी। इसके माध्यम से आदिवासियों को रोजमर्रा की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले सामान भी सही दर पर उपलब्ध हो सकेगे।

दिनांक – 29/04/2013 रात्रि विश्राम बाँसवाड़ा

दिनांक – 30/04/2013

राजकीय जनजाति बालिका आश्रम छात्रावास, बड़ौदिया, बागीदोरा, जिला – बाँसवाड़ा का उद्घाटन।

दिनांक – 30/04/2013 को प्रातः 10 बजे अध्यक्ष महोदय ने ग्राम – बड़ौदिया, पंचायत समिति – बागीदौरा स्थित जनजाति बालिका आश्रम छात्रावास के नव निर्मित भवन का उद्घाटन किया। यह छात्रावास जनजाति क्षैत्रीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा केन्द्रीय प्रवर्तित योजना के अन्तर्गत रूपये 1.77 करोड़ राशि से तैयार किया गया है। जिसकी क्षमता 50 छात्राओं की है। इस अवसर पर आयोग के अध्यक्ष महोदय ने उपस्थित जन समुदाय को सम्बोधित करते हुए कहा कि राजस्थान सरकार द्वारा जनजाति विकास व कल्याण के लिए संचालित योजनाओं का लाभ उठाये। उन्होने राजस्थान सरकार द्वारा आमजन के लिए लागू की गई योजनाओं की प्रंशसा की। राज्य के जनजाति विकास मंत्री श्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीय ने इस अवसर पर अपने उद्बोधन में कहा कि राजस्थान सरकार 1 रूपये प्रति किलो की दर से बी.पी.एल. परिवारों को गेहुँ उपलब्ध करा रही है। नरेगा में 100 दिन वर्ष में मजदूरी प्रदान करने को बढ़ाकर 150 दिन कर दिया है। जननी सुरक्षा योजना के तहत प्रसवपूर्व व प्रसवोत्तर सुविधाऐं राज्य सरकारप्रदान कर रही है। मुफ्त दवाऐं व जांच की सुविधा सरकार द्वारा प्रदान की जा रही है। पशुओं की बीमारी की दवाईयाँ भी सरकार द्वारा निःशुल्क दी जा रही है। वृद्धावस्था तथा विधवा महिला पेंशन प्रदान की जा रही है। जनजाति क्षेत्र में रहने वाले अन्य सामान्य वर्ग के लिए पृथक से 200 करोड़ रूपये की राशि व्यय कराने

Rameshwar Oraon

Dr. RAMESHWAR ORAON
Chairperson
National Commission for Scheduled Tribes
Govt. of India
New Delhi

(630)

का बजट में प्रावधान किया गया है। मंत्री महोदय ने आश्रम छात्रावास परिसर में ही आवासीय विद्यालय खोलने के लिए 2 करोड़ रूपये मुहैया कराने की भी घोषणा की। इस अवसर पर आयोग के सदस्य श्री भैरूलाल मीणा ने ग्रमीणों से कहा कि सरकारी प्रयासों का लाभ लेकर विकास हमारी अपनी जिम्मेदारी है। इसलिए तरक्की पाने के लिए हम खुद पहल कर आगे आयें व अपने को किसी से निर्बल नहीं समझे। कार्यक्रम में बड़ौदिया निवासी – वैशाली जोशी को कक्षा 12वीं में राज्य स्तर पर सातवाँ स्थान प्राप्त करने पर आयोग अध्यक्ष महोदय ने सम्मानित किया तथा मंत्री महोदय ने छात्रा को स्कूटी देने की घोषणा की।

समारोह में जिला प्रमुख रेशम मालवीया ने महिलाओं को आव्हान किया कि वे अपनी बालिकाओं को नियमित विद्यालय भेजें। उन्होने कहा कि महिलाऐं अपने क्षेत्र के विकास में भागीदारी निभा रही है।

ग्राम – पाटिया, गलिया (आनन्दपुरी) में पाटिया गलिया टाण्डी माइनर का शिलान्यास :–

आयोग के माननीय अध्यक्ष ने पाटिया गलिया में नहर निर्माण की आधारशिला रखी। इस नहर के निर्माण पर 425.56 लाख रूपये की लागत आयेगी। नहर से क्षैत्र के 535 हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई हो सकेगी। नहर की लम्बाई 11 किमी है। इस नहर से जनजाति बाहुल्य ग्राम – पाटिया गलिया, टाण्डी, परवाली बोराखण्डी तथा दलपुरा लाभान्वित होगें। इस अवसर पर ग्रामीणों को सम्बोधित करते हुए अध्यक्ष महोदय ने कहा कि जनजाति उपयोजना क्षेत्र उदयपुर व बाँसवाड़ा में अपने वर्तमान दौरे के दौरान **उन्होने पाया कि क्षेत्र की सड़कों की स्थिति बहुत अच्छी है।** जबकि अकसर ऐसा पाया जाता हैं कि दूरदराज ग्रामीण जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में सड़को की दशा बहुत खराब है। इससे राजस्थान सरकार द्वारा किये गये कार्यो की गुणवता परिलक्षित होती है। जिसके लिए राजस्थान सरकार की उन्होने प्रशंसा की। इस मौके पर आयोग के माननीय सदस्य श्री भैरूलाल मीणा बागीदौरा पंचायत समिति के प्रधान श्री सुभाष लम्बोलिया, प्रधान आनन्दपुरी वेल जी भाई सैन्ट्रल कोऑपरेटिव बैंक की अध्यक्ष शांता गरासिया, समाजसेवी चांदमल जैन, बागीदौरा के विकास अधिकारी श्री विवेक कछावा, आई.सी. डी.एस. की उपनिदेशक श्रीमती लीला सहित क्षेत्र के जिला परिषद्, पंचायत समीति के सदस्य तथा ग्राम पंचायतो के सरपंच भी उपस्थित थे। तत्पश्चात् अध्यक्ष महोदय ने ग्राम छाजा में बारादारी भवन का उद्‌घाटन किया व जनसमूह को सम्बोधित किया।

मानगढ़ धाम (आनन्दपुरी) का अवलोकन –

दिनांक – 30/4/2013 को साँय 6.00 बजे अध्यक्ष व सदस्य महोदय ने पंचायत समिति आनन्दपुरी अन्तर्गत स्थित मानगढ़ धाम का अवलोकन किया। इस स्थान का ऐतिहासिक महत्व है व देश के स्वाधीनता आन्दोलन से जुड़ा है। इस स्थान पर गोविन्द गुरू के नेतृत्व में स्वाधीनता आन्दोलन वर्ष 1913 में अपने यौवन पर था। 17 नवम्बर, 1913 में गोविन्द गुरू के नेतृत्व में आदिवासी लोग इस जंगल पर आकर बैठ गये थे और कहा था कि इस देश से अंग्रेजों को निकाल कर आजाद करा कर दम लेगें। दिनांक – 17 नवम्बर, 1913 को प्रातः 7.

Rameshwar Oraon
Dr. RAMESHWAR ORAON
Chairperson
National Commission for Scheduled Tribes
Govt. of India
New Delhi

10 बजे फौज द्वारा गोली चलाई जिससे 1500 देश भक्त (अधिसंख्यक आदिवासी) वही शहीद हो गये। उन्ही की याद में इस स्थल को एक धाम व शहीद स्थल के रूप में विकसित किया गया हैं अध्यक्ष महोदय ने मानगढ़ धाम में गोविन्द गुरू की प्रतिमा को पुष्पहार पहनाया तथा शहीद स्मारक पर मानगढ़ कांड के शहीदो के प्रति भावभीनी श्रद्धाजंली अर्पित की। अध्यक्ष ने मानगढ़ की धरती को ऐतिहासिक व आने वाली पीढ़ियो के लिए प्रेरणा दायक बताया। अध्यक्ष महोदय ने इस स्थल को ऐतिहासिक व र्प्यटक स्थल के रूप में पूर्ण रूप से विकसित करने के लिए किये जा रहे निरन्तर प्रयासों के लिए माननीय मंत्री श्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीय एवं राजस्थान सरकार की सराहना की तथा इसे पूर्ण रूप से पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने की आवश्यकता बताई। इस अवसर पर इस स्थल के ऐतिहासिक महत्व की जानकरी विभिन्न शैक्षणिक व अन्य पाठ्यक्रमों में सम्मिलित किये जाने की आवश्यकता भी बताई गई। जिससे इस स्थान के महत्व की जानकारी जन–जन तक पहुँच सके व स्वतन्त्रता आन्दोलन में आदिवासियों के योगदान एवं बलिदान को स्मरण किया जा सकें।

दिनांक – 30/04/2013 रात्रि विश्राम – ग्राम नाहरपुरा

दिनांक – 01/05/2013

बाँसवाड़ा जिले के जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक

माननीय अध्यक्ष एवं सदस्य महोदय दिनांक – 01/05/2013 को प्रातः 10.30 बजे कार्यालय जिला कलक्टर, बांसवाड़ा पहुँचे। जहाँ श्री के. वी. गुप्ता, कलक्टर, श्री वी. सी. गर्ग, अतिरिक्त जिला कलक्टर, श्रीमती रेशम मालवीया, जिला प्रमुख, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद बाँसवाड़ा द्वारा स्वागत किया गया। तत्पश्चात् जिला परिषद सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक की गई जिसका विवरण निम्नवत है।

बैठक की शुरूआत जिला कलक्टर, बाँसवाड़ा द्वारा करते हुए कहा कि यह बाँसवाड़ा जिले का सौभाग्य है कि आयोग के माननीय अध्यक्ष डॉ. उराँव व माननीय सदस्य श्री भैरूलाल मीना यहाँ पद्यारे एवँ वांगड़ धरती पर क्षेत्र का भ्रमण कर जनमानस की भावनाओं को देखा परखा है तथा आदिवासी विकास की जानकारी प्राप्त की। कलक्टर ने बताया कि बाँसवाड़ा, जिला रेल मार्ग से वंचित है। उसे रतलाम से डूँगरपुर होते हुए जोड़ने हेतु राज्य सरकार ने 50 प्रतिशत सहयोग देकर 1 हजार 25 करोड़ रूपये राशि का योगदान दिया है। बाँसवाड़ा जिले में दो पावर प्लान्ट व एक न्यूक्लियर पावर प्लान्ट लगाने की कार्यवाही की जानकारी थी। जिले में 50 प्रतिशत जनसंख्या बी.पी.एल. है। जिसे प्रंतिमाह 25 किलो अनाज 1 रूपये प्रतिकिलो दर से उपलब्ध कराया जा रहा है। शेष 50 प्रतिशत एपीएल परिवारों को 5/– प्रतिकिलो आटा उपलब्ध कराया जा रहा है।

Rameshwar Oraon

Dr. RAMESHWAR ORAON
Chairperson
National Commission for Scheduled Tribes
Govt. of India
New Delhi

राष्ट्रीय आजिविका मिशन के माध्यम से कौशल विकास कार्यक्रम द्वारा बेरोजगार युवक–युवतियों को प्रशिक्षण दिलाया जाकर 5 से 7 हजार पाँच सौ रूपये राशि दिये जाने की जानकारी दी। जिले में 45 आश्रम छात्रावास संचालित होने की भी जानकारी दी गई।

जिला कलक्टर ने जिले के विभिन्न विभागों में अधिकारियों/कर्मचारियों के बड़ी संख्या में पद रिक्त होने से आशानुरूप उपलब्धियाँ अर्जित करने में आ रही समस्या की ओर ध्यान आकृष्ट किया।

कलक्टर महोदय के प्रारम्भिक सम्बोधन के पश्चात् आयोग अध्यक्ष महोदय ने विभिन्न विभागों/विषयों पर निम्न विवरणानुसार समीक्षा की।

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतिकरण योजना –

अध्यक्ष महोदय ने राजीव गांधी विद्युतिकरण योजना के तहत क्षैत्र में विशेष रूप से आनन्दपुरी क्षेत्र में विद्युतिकरण का कार्य नहीं होने के सम्बन्ध में जानना चाहा। इस सम्बन्ध में अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के अधीक्षण अभियन्ता ने बताया कि हैदराबाद की एक कम्पनी आईसीएफए इंडिया लिमिटेड को यह कार्य दिया गया लेकिन कम्पनी की आन्तरिक समस्यावश उसने यह काम करना बन्द कर दिया। कम्पनी द्वारा जिले में 28 प्रतिशत ही काम किया जा सका। निगम द्वारा दूसरी कम्पनी से यह कार्य कराने की कार्यवाही प्रक्रिया जारी है। माननीय अध्यक्ष ने ग्रामीण विद्युतीकरण पर जिला प्रशासन, सम्बन्धित विभाग व राज्य सरकार के स्तर पर विशेष ध्यान दिये जाने की आवश्यकता बताई। पूर्व कम्पनी द्वारा किये गये कार्य की प्रगति का विवरण सलंग्न परिशिष्ट – 1 पर है।

शिक्षा –

माननीय अध्यक्ष ने जिले में माडल एकलव्य स्कूल की जानकारी चाही। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा बताया गया कि पंचायत समिति घाटोल क्षेत्र के गाँव रूपजी का खेड़ा में 280 लाख रूपये की लागत से सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से उक्त मॉडल स्कूल भवन का कार्य प्रगति पर है अध्यक्ष महोदय ने जिले में और एकलव्य मॉडल स्कूल खोले जाने की आवश्यकता बताई। 5 अन्य मॉडल स्कूल स्वीकृत होने की भी जानकारी दी गई लेकिन किन्ही कानूनी अड़चनों के कारण इन पर कार्य नहीं होने के बारे में बताया। विद्यालयों में शिक्षकों के पद रिक्त होने की स्थिति के बारे में अध्यक्ष महोदय द्वारा ज्ञात करने पर शिक्षा विभाग के अधिकारी ने बताया कि प्राथमिक, उच्च प्राथमिक व माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में करीब 20 प्रतिशत पद शिक्षकों के रिक्त है। अध्यक्ष महोदय ने रिक्त पदों को भरने हेतु विशेष प्रयास किये जाने की आवश्यकता बतायी। बैठक में मौजूद माननीय मंत्री जनजाति विकास विभाग, राजस्थान सरकार ने शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में न्यायालयों में दायर वादों के कारण कठिनाई आने से अध्यक्ष महोदय को अवगत कराया। राज्य सरकार द्वारा शिक्षकों की भर्ती की कार्यवाही जारी होने की जानकारी माननीय मंत्री महोदय ने दी।

Dr. RAMESHWAR ORAON
Chairperson
National Commission for Scheduled Tribes
Govt. of India
New Delhi

<u>वन अधिकार –</u>

माननीय अध्यक्ष ने जिले में वन अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त क्लेम तथा उनके निष्पादन की प्रगति के बारे में पूछने पर बताया गया कि 16 हजार 699 क्लेम प्राप्त हुए जिनसे से 197 निरस्त किये गये। जनजाति मंत्री ने पूरे राज्य की स्थिति से अध्यक्ष महोदय को अवगत कराते हुए बताया कि प्रदेश में 60 हजार में से 42 हजार परिवारों को वन अधिकार पट्टे जारी किये जा चुके है। जिस पर अध्यक्ष महोदय ने संतोष व्यक्त करते हुए अन्य राज्यों की तुलना में राजस्थान की स्थिति ठीक होना बताया। उन्होंने विभाग को निर्देश दिये कि कोई भी पात्र परिवार वन अधिकार पट्टे से वंचित नहीं रहना चाहिये। आदिवासियों के जंगल से जुड़े अधिकारों के बारे में पूछने पर बताया गया कि आदिवासियों को जंगल से सूखी लकड़ी संकलन, गाय, भैंस, बकरी इत्यादि को चारागाह हेतु अनुमति तथा तेन्दू पता, महुआ, गोंद इत्यादि लघु वन उपज संग्रहण राजससंघ के माध्यम से कराने की जानकारी दी गई।

<u>चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग</u>

अध्यक्ष महोदय ने जिले में चिकित्सको के रिक्त पदों के बारे में विभाग के अधिकारी से स्थिति बताने को कहा। विभागीय अधिकारी ने बताया कि चिकित्सा अधिकारी के 40 पद खाली है। कनिष्ठ विशेषज्ञ पद पर मात्र 9 डाक्टर कार्यरत है। अध्यक्ष महोदय द्वारा ए.एन.एम. के अपने मुख्यालयों पर रहने की स्थिति के बारे में बताया गया कि करीब 70 प्रतिशत अपने मुख्यालयों पर रहती है। मोबाईल यूनिट्स के बारे में पूछने पर बताया कि जिले में 8 मेडीकल मोबाईल यूनिट्स कार्यरत है जो एन. जी. ओ. के माध्यम से संचालित है। अध्यक्ष महोदय ने मोबाईल मेडीकल सुविधा आदिवासी दूर–दराज इलाको में उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु स्थानीय जन प्रतिनिधियों की भागीदारी की आवश्यकता बताई। आशा सहयोगिनियों को मेडीकल किट उपलब्ध होने के बारे में बताया गया कि पर्याप्त मेडीकल किट उपलब्ध कराये गये है। **<u>माननीय अध्यक्ष द्वारा राजस्थान की निःशुल्क दवाई व जांच की योजना तथा जननी सुरक्षा योजना का आदिवासियों को पूरा फायदा पहुँचाने हेतु विभाग व जिला प्रशासन को सतर्कता बरतने के लिए कहा।</u>**

विभागीय अधिकारियों ने बताया कि जिले में एम. एम. आर. की दर 364, आइ. एम. आर 62 व सी.बी.आर. 30.8 है। लिंग अनुपात 975 है। जिले में 1 जिला अस्पताल, 6 शहरी औषधालय, 17 सी. एच. सी., 5. पी.एच.सी. व 469 उप–स्वास्थ्य केन्द्र है। **<u>अध्यक्ष महोदय ने चिकित्सों व पैरा मेडीकल स्टाफ के रिक्त पदों को शीघ्र भरे जाने के प्रयास करने करने हेतु विभाग को निर्देशित किया।</u>**

Rameshwar Oraon

Dr. RAMESHWAR ORAON
Chairperson
National Commission for Scheduled Tribes
Govt. of India
New Delhi

स्वरोजगार :

राजस्थान आजिविका मिशन के परियोजना अधिकारी द्वारा बेरोजगार युवक–युवतियों को विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षित कर 5 हजार से 7 हजार 500 तक भत्ता प्रदान करने की जानकारी दी। अध्यक्ष महोदय ने सुझाव दिया कि जिले में क्षैत्र एवं गाँवों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बिजली, मिस्त्री, मैशन, कारपेन्टरी जैसे कार्यो में स्थानीय स्तर पर ही आदिवासी युवकों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिये।

लीड बैंक मैनेजर द्वारा भी स्वरोजगार प्रशिक्षण माध्यम से जिलो में विभिन्न व्यवसायों में आवासीय प्रशिक्षण दिये जाने की जानकारी दी। माननीय अध्यक्ष महोदय ने उड़ीसा राज्य का उदाहरण देते हुए बताया कि वहाँ पर 10 हजार युवक – युवतियों को आवासीय विद्यालयों में अध्ययन के साथ – साथ अलग – अलग व्यवसायों में प्रशिक्षित किया जा रहा है। इसी तरह राजस्थान में भी किया जाना चाहिये। अध्यक्ष महोदय ने कृषि तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराने के साथ एग्रोबेस यथा मुर्गी पालन, दुग्ध उत्पादन इत्यादि की ओर रूझान बढ़ाने की आवश्यकता बताई।

मनरेगा –

अधिशासी अभियन्ता मनरेगा द्वारा जिले में कुल 3 लाख 13 हजार 998 परिवारों के जाब कार्ड धारक होने की जानकारी थी। श्रमिकों को भुगतान बैंक/लैम्पस खातों के माध्यम से किये जाने के बारे में बताया। राज्य सरकार द्वारा अब 100 दिन से बढ़ाकर 150 दिन वर्ष में मजदूरी प्रदान करने की जानकारी दी गई। इसके अतिरिक्त 100 दिन मजदूरी करने वाले को 2100/– पृथक से स्वरोजगार हेतु प्रेरित करने के लिए दिये जाने के बारे में बताया। अध्यक्ष महोदय ने 150 दिन मजदूरी प्रदान करने के राज्य सरकार के निर्णय की सराहना की। उन्होने कहा कि भारत सरकार द्वारा मजदूरी दिन बढ़ाने की कार्यवाही से पहले राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया जो प्रंशसनीय है। उन्होने कहा कि आयोग द्वारा भी केन्द्र सरकार को इस आशय का सुझाव दिया गया था।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग –

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अधिकारी ने बताया कि वर्ष 2012–13 में 13270 अनुसूचित जनजाति छात्र/छात्राओं को 343.18 लाख रूपये उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति के रूप में दिये गये। उन्होने बताया कि राज्य में छात्रवृत्ति वितरण का कार्य **ऑनलाईन** कर दिया गया है। किसी भी प्रकार की आवेदन में त्रुटि पाये जाने पर सूचना सम्बन्धित छात्र को उसके मोबाईल पर दी जाती है। छात्रवृत्ति बैंक खाते में डाली जाती है। अध्यक्ष महोदय ने पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति के बारे में पूछा जिस पर बताया गया कि वर्ष 2012–13 में 469.63 लाख रूपये राशि 61108 अनुसूचित जनजाति को पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति के रूप में वितरित की। अध्यक्ष महोदय ने

Dr. RAMESHWAR ORAON
Chairperson
National Commission for Scheduled Tribes
Govt. of India
New Delhi

राजस्थान में अन्य राज्यों की अपेक्षा छात्रावासों की स्थिति, सुविधाओं तथा प्रति छात्र प्रदान की जाने वाली राशि अच्छी बताई।

<u>पुलिस विभाग –</u>

जिले के पुलिस अधीक्षक श्री डी. एस. चूंडावत ने बताया कि वर्ष 2010–11 से 2012–13 तक अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत दर्ज 33 प्रकरणों में से 23 प्रकरण अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित है। जिनमें स्वीकृत मानदण्ड अनुसार आर्थिक सहायता प्रदान की गई है व प्रकरण विशिष्ट न्यायालय अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण बाँसवाड़ा में विचाराधीन है। अध्यक्ष महोदय ने पुलिस विभाग में रिक्त पदों के बारे में पूछने पर बताया गया कि रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। कुछ पद पदोन्नति के माध्यम से भरे जाने की सम्भावना है।

<u>अध्यक्ष महोदय ने कहा कि कानून व्यवस्था की दृष्टि से पुलिस विभाग में पर्याप्त कार्मिक होने आवश्यक है। इस हेतु विशेष प्रयासों की आवश्यकता है।</u>

<u>खाद्य एवं आपूर्ति –</u>

जिला रसद अधिकारी द्वारा जिले में बीपीएल एवं एपीएल परिवारों को उपलब्ध कराये जा रहे गेहुँ की विस्तृत जानकारी दी गई। जिस पर माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा राज्य सरकार के प्रयासो पर संतोष व्यक्त किया तथा अन्य राज्यों की तुलना में इसे बेहतर बताया।

माननीय अध्यक्ष महोदय ने बैठक के अन्त में जिले में विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को भरने हेतु उपाय एवं सुझाव मांगे। जिला कलक्टर ने बताया कि सेवानिवृत्त कार्मिको को लगाने से कुछ हद तक समाधान हो सकता है। **<u>जनजाति उपयोजना क्षेत्र में स्वीकृत पदो का अलग कैडर बनाने तथा अलग से भत्ते निर्धारित करने हेतु राज्य सरकार को प्रस्ताव भिजवाने हेतु कहा।</u>**

बैठक के अन्त में अतिरिक्त कलक्टर, जिला – बांसवाड़ा द्वारा सभी का आभार व्यक्त करते हुए बैठक समाप्त की। जिला स्तरीय समीक्षा बैठक में उपस्थित अधिकारियों की सूची **<u>परिशिष्ट – 2</u>** पर सलंग्न है। आयोग द्वारा जिला प्रशासन को उपलब्ध करायी गई प्रश्नावली का बिन्दुवार जवाब **<u>परिशिष्ट – 3</u>** पर है।

<u>स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक –</u>

सांय – 4 बजे सर्किट हाउस, बांसवाड़ा में जिले के स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई। जिसमें स्थानीय विधायक ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों तथा जिला परिषद के प्रतिनिधियों, स्थानीय नागरिकगण व समाजसेवी गण ने भाग लिया।

Rameshwar Oraon

Dr. RAMESHWAR ORAON
Chairperson
National Commission for Scheduled Tribes
Govt. of India
New Delhi

बैठक में निम्न बिन्दुओं पर अध्यक्ष महोदय का ध्यान आकृष्ट किया गया।

1. वन क्षेत्र में आने वाली भूमि पर मार्बल खदान हेतु लगभग 27 वर्ष पूर्व किये गये 200 आवेदनों को वनक्षेत्र में होने के कारण खारिज़ कर दिया गया। जबकि दूसरी ओर आर. के. मार्बल कम्पनी को अनुमति दे दी गई। **इसे क्षेत्र के आदिवासी लोगों के अधिकारों का हनन बताते हुए आयोग के माननीय अध्यक्ष महोदय ने मामले को आयोग मुख्यालय स्तर पर दिखवाते हुए यथोचित कार्यवाही करने का आवश्वासन दिया।**
2. आदिवासियों की खेती की जमीनो को भूमाफियाओं द्वारा बचाया जाये। अध्यक्ष महोदय ने इस सम्बन्ध में राजस्व अधिकारियों द्वारा जमीन हस्तान्तरण, पंजीकरण व नामान्तरण खोलने की कार्यवाही से पूर्व पूर्ण सर्तकता बरतने की आवश्यकता बतायी।
3. जनजाति आयुक्त का पद अलग होना चाहिये। वर्तमान में सम्भागीय आयुक्त, उदयपुर ही आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग भी होता है। अध्यक्ष महोदय ने इससे असहमति व्यक्त करते हुए कहा कि सम्भागीय आयुक्त का पद अलग करने से आयुंक्त टीएडी के अधिकारी कम हो जायेगें। ज़िससे विपरित प्रभाव पड़ेगा।
4. जनजाति उपयोजना क्षेत्र में क्रियान्वित योजनाओं का सही प्रकार से फॉलोअप होना चाहिये। अध्यक्ष महोदय ने जनजाति उपयोजना की राशि के डाईवर्जन पर रोक की आवश्यकता बताई तथा इस सम्बन्ध में आन्ध्रप्रदेश सरकार के प्रयासों का उदाहरण देते हुए विभाग द्वारा इसे सुनिश्चित किये जाने हेतु निर्देश दिये।
5. जनजाति परामर्शदात्री समीति द्वारा की गई सिफारिशो पर कार्यवाही होनी चाहिये। अध्यक्ष महोदय ने समीति की सिफारिशों पर कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु टीएडी विभाग को निर्देश दिये।
6. प्रस्तावित जनजाति विश्वविद्यालय का नाम जनजाति के किसी विख्यात व्यक्ति के नाम से होना चाहिये। माननीय अध्यक्ष ने इस आशय का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजने हेतु जिला प्रशासन को निर्देशित किया।
7. जनजाति उपयोजना क्षेत्र की जमीनो का रिकॉर्ड अपडेट होना चाहिये। इस सम्बन्ध में जिला प्रशासन व टीएडी विभाग द्वारा उपयुक्त कार्यवाही करने हेतु अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिये।
8. माही विस्थापितों के पुर्नस्थापन के मामलों का त्वरित रूप से निपटारा किया जाना चाहिये। अध्यक्ष महोदय ने विस्थापितों के पुर्नस्थापना के मामलों को अविलम्ब निष्पादन करने हेतु जिला प्रशासन को निर्देश दिये।
9. जनजाति उपयोजना क्षेत्र में अन्य वर्ग के लिए 200 करोड़ रूपये के पैकेज पर आपत्ति प्रकट की गई। अध्यक्ष महोदय ने की गई आपत्ति पर असहमति व्यक्त की।
10. जनजाति उपयोजना क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति के लिए स्केल 1 से 9 तक राजकीय सेवाओं के पदों में 45 प्रतिशत आरक्षण को स्केल 13 तक बढ़ाने की माँग की गई। इस सम्बन्ध में परीक्षण करने हेतु टीएडी विभाग को निर्देशित किया गया।

आयोग के अध्यक्ष महोदय ने सभी उपस्थित जनप्रतिनिधियों द्वारा बैठक में जनजाति क्षेत्र से सम्बन्धित समस्याओं पर रखे विचारों की सराहना की व आयोग के माध्यम से जिला प्रशासन

Rameshwar Oraon

Dr. RAMESHWAR ORAON
Chairperson
National Commission for Scheduled Tribes
Govt. of India
New Delhi

व राज्य सरकार से इन पर यथोचित कार्यवाही करने का अनुरोध किया।बैठक में उपस्थित जनप्रतिनिधियों की सूची **परिशिष्ट – 4** पर सलंग्न है।

आयोग के माननीय अध्यक्ष के जिला उदयपुर व बांसवाड़ा के राजकीय प्रवास के दौरान विभिन्न दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचार कतरनों की छायाप्रतियाँ **परिशिष्ट – 5** पर है।

आयोग मुख्यालय स्तर पर कार्यवाही योग्य प्राप्त अभ्यावेदनों को अध्यक्ष महोदय ने आयोग की उपनिदेशक श्रीमती के. डी. बन्सौर को कार्यवाही हेतु दिये तथा आयोग क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर स्तर से कार्यवाही योग्य अभ्यावेदन श्री वी. पी. सिंहल, अनुसंधान अधिकारी को उचित कार्यवाही हेतु दिये।

दिनांक – 25/5/2013 को अध्यक्ष महोदय ने सांय वायुयान द्वारा उदयपुर से दिल्ली के लिए प्रस्थान किया। आयोग के माननीय सदस्य श्री भैरू लाल मीणा दिनांक – 05/05/2013 को उदयपुर से दिल्ली गये।

श्री वी. पी. सिहंल, अनुसंधान अधिकारी आयोग क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर सम्पूर्ण दौरे में अध्यक्ष एवं सदस्य महोदय के साथ रहे।

***

Rameshwar Oraon.

Dr. RAMESHWAR ORAON
Chairperson
National Commission for Scheduled Tribes
Govt. of India
New Delhi